International Journal of Humanities and Education Research

ISSN Print: 2664-9799
ISSN Online: 2664-9802
Impact Factor: RJIF 8.2
IJHER 2023; 5(2): 45-48
www.humanitiesjournal.net
Received: 01-05-2023
Accepted: 05-06-2023

सरिता
एसोसिएट प्रोफेसर शिक्षा विभाग
अदिति महाविद्यालय, दिल्ली
विश्वविद्यालय, दिल्ली, भारत

Corresponding Author:
सरिता
एसोसिएट प्रोफेसर शिक्षा विभाग
अदिति महाविद्यालय, दिल्ली
विश्वविद्यालय, दिल्ली, भारत

बेटियों के सामाजिक समावेशन में ग्राम पंचायत की भूमिका

सरिता

DOI: https://doi.org/10.33545/26649799.2023.v5.i2a.72

सारांश
भारत में स्त्रियां बहुत से क्षेत्रों से बर्हिवेशित हैं। स्त्रियों की सामाजिक कार्यकलापों में भागीदारी भी बहुत से क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में सीमित है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो यह स्थिति और भी खराब है। इस शोध लेख में 11 से 18 वर्ष की बेटियों के सामाजिक समावेशन में ग्राम पंचायत की भूमिका का अध्ययन किया गया है। इसमें ग्राम पंचायत ने समावेशन संबंधी क्या–क्या कार्य किए, उसकी क्या नीति एवं योजनाएं रही एवं कैसे इनका कार्यान्वयन किया गया, इन प्रमुख शोध प्रश्नों के साथ यह शोध किया गया है। गुणात्मक शोध पद्धति को शोध कार्य में अपनाया गया है। यह शोध कार्य हरियाणा प्रदेश के एक जिले पर आधारित है जिसमें बाल, लिंगानुपात की स्थिति सबसे खराब थी। इस शोध में पाया गया कि गांव में बेटियों के समावेशन के संबंध में ग्राम पंचायत का ढीला–ढाला रवैया है एवं ग्राम पंचायत एक प्रभावी भूमिका नहीं निभा रही है। ग्राम पंचायत के और अधिक उत्तरदायित्व हैं और इसकी भूमिका बेटियों के सामाजिक समावेशन में और अधिक प्रभावित हो सकती है।

कुटशब्दः बेटियां, समावेशन, ग्राम पंचायत, सशक्तीकरण

प्रस्तावना
यह शोध हरियाणा प्रदेश के एक जिले में किया गया है जिसका बाल–लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम है तथा स्त्री–पुरुष साक्षरता में बहुत ज्यादा अंतर है। इस शोध के करने के पीछे कुछ प्रमुख प्रश्न रहे जिसके आधार पर उद्देश्यों का निर्माण किया गया।

शोध के प्रमुख उद्देश्य
- गांव में बेटियों के सामाजिक समावेशन की स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना।
- ग्राम पंचायत की भूमिका का बेटियों के समावेशन की दृष्टि से अध्ययन करना।
- ग्राम पंचायत द्वारा बेटियों के सामाजिक समावेशन से संबंधित किए गए कार्यों एवं कार्यान्वित योजनाओं एवं नीतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना।
- गांव में बेटियों के बेहतर सामाजिक समावेशन हेतु सुझाव देना।

शोध का औचित्य
यह शोध हरियाणा प्रदेश के झज्जर जिले में किया गया है। लड़कियों के विद्यालयी समावेश संबंधी शोध तो हुए हैं परंतु गांवों में रहने वाली बेटियों की सामाजिक समावेशन की स्थिति कैसी है और उनके सामाजिक समावेशन में ग्राम पंचायत की क्या भूमिका है इस संबंध में शोध नहीं हुए हैं। अतः यह शोध कार्य गांव में रहने वाली बेटियों के सामाजिक समावेशन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण बन जाता है। यह शोध गांव में रहने वाली बेटियों के सामाजिक समावेशन की समझ में बढ़ावा देने के साथ–साथ सरकारी तंत्र के प्रभावी कार्यान्वयन में भी सहायक सिद्ध होगा। इस शोध कार्य से शैक्षिक समझ में बढ़ोतरी होगी क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बेटियों की शैक्षिक स्थिति कैसी है यह शोध इस पर भी है। अतः यह शोध कार्य अति महत्त्वपूर्ण है।

शोध पद्धति
इस शोध कार्य में गुणात्मक पद्धति को अपनाया गया है जिसमें शोध उपकरण के रूप में साक्षात्कार, अवलोकन, अनौपचारिक बातचीत को अपनाया गया है। आंकड़े एकत्रित करने के लिए बेटियों, ग्रामीण एवं ग्राम पंचायत सदस्यों से साक्षात्कार लेकर प्राप्त किए गए हैं। इसी प्रक्रिया में अवलोकन भी किया गया है और अनौपचारिक बातचीत से भी आंकड़े लिए गए हैं।

न्यादर्श

इस शोध में 11 से 18 वर्ष तक की 100 बेटियों, 55 ग्रामीण एवं 5 ग्राम पंचायत सदस्यों को लिया गया है एवं इनसे साक्षात्कार, अवलोकन एवं अनौपचारिक बातचीत से आंकड़े एकत्रित किए गए हैं।

आंकड़ों का विश्लेषण, निष्कर्ष एवं सुझाव

गांव में बेटियों के सामाजिक समावेशन की स्थिति।

शोध में पाया गया कि गांव की 100 प्रतिशत बालिकाओं का किसी न किसी विद्यालय में नामांकन है। चाहे वह सरकारी स्कूल हो या निजी। अतः शैक्षिक समावेशन की स्थिति नामांकन की दृष्टि से तो बेहतर है। गांव में बेटियों के लिए स्कूल स्वयं में बहुत बड़ा और लगभग अकेला बाहरी दुनिया से निरंतर संपर्क का माध्यम है। 97 प्रतिशत बेटियां स्कूल जाना पसंद करती हैं। उन्हें स्कूल का माहौल, वहां के शिक्षक–शिक्षिकाओं का प्रेम, व्यवहार एवं पढ़ाने का ढंग, सहेलियों से मिलना सभी पसंद हैं और घर से बाहर जाने की आजादी मिलती है। इस संदर्भ में निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि गांव में स्कूल की भूमिका बेटियों के सामाजिक एवं शैक्षिक समावेशन में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण बन जाती है।

गांव में बालिकाओं को घर से बाहर अकेले जाने की अनुमति नहीं है। शोध में पाया गया कि किशोरी बालिकाएं घर से या तो किसी व्यस्क सदस्य जैसे दादी इत्यादि के साथ बाहर निकलती हैं या समूह में स्कूल जाती हैं। गांव में बेटियों के सामाजिक समावेशन की स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई। बेटियां अधिकांशतः पाबंदियों में रहती मिली। उनको बेटों के समान स्वतंत्रता एवं समानता नहीं थी। बेटियों को निर्णय लेने, पहल करने की स्वतंत्रता नहीं थी। उनके संबंध में सभी निर्णय सामाजिक पक्षपात जिसमें लिंग आधारित पक्षपात सम्मिलित हैं, के आधार पर अभिभावक लेते थे।

बेटियों के सामाजिक समावेशन में ग्राम पंचायत की भूमिका

गांव में बेटियों की स्वतंत्रता एवं समानता के अधिकारों को दिलाने एवं उनके प्रति अभिभावकों एवं ग्रामीणों का दृष्टिकोण सकारात्मक करने में ग्राम पंचायत की भूमिका प्रभावित हो सकती है। परंतु इस शोध में पाया गया कि स्वयं ग्राम पंचायत भी पितृसत्तात्मक समाज की बेड़ियों से मुक्त नहीं है। स्वयं ग्राम पंचायत में ही स्त्री पंचायत सदस्यों का सच्चे अर्थों में समावेशन नहीं हुआ है। शोध में पाया गया कि ग्राम पंचायत की स्त्री सदस्यों का कार्य उनके पति करते थे और स्त्री सदस्यों को गांव में बेटियों की स्थिति, समस्याओं की जानकारी नहीं थी। ग्राम पंचायत बेटियों के लिए क्या कार्य कर सकती हैं, उनके क्या अधिकार एवं कर्तव्य होते हैं किसी भी प्रकार की कोई जानकारी एवं समझ उनको नहीं थी।

निष्कर्ष रूप में यह पाया गया कि ग्राम पंचायत का कोई फोकस बेटियों के सामाजिक समावेशन पर नहीं है। ग्राम पंचायत समाज की पितृसत्तात्मक सोच को सही मानती है एवं उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना चाहती। बेटियों की स्वयं के लिए निर्णय लेने की स्वतंत्रता उनको नहीं देने के पक्ष में है। बेटियों को क्या करना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैसे कार्य करने चाहिए, अच्छी आदर्श बेटी कौन है, ऐसे प्रश्नों की प्रतिक्रिया में ग्राम पंचायत की सोच ग्रामीणों जैसी ही थी। चाल–चलन ठीक हो, अभिभावकों का कहना माने, अभिभावकों की पसंद के लड़के से विवाह करें, इत्यादि दृष्टिकोण ग्राम पंचायत का शोध में पाया गया।

स्पष्ट है कि गांव में बेटियों के प्रभावी सामाजिक समावेषन के लिए गांव की पंचायत को अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करना चाहिए। बेटियों को बेटों के समान केवल कथन से ही नहीं व्यवहार में भी गांव में सत्य सिद्ध करने की दिशा में कार्य करने चाहिए। ग्राम पंचायत को स्वयं ग्रामीणों में जागरूकता को बढ़ाने की दिशा में निरंतर कार्य करना चाहिए। बालिकाओं को स्थानीय स्तर पर आत्मविश्वास विकसित करने में सहायता एवं उनको समर्थन देना चाहिए।

ग्राम पंचायत द्वारा बेटियों के सामाजिक समावेशन से संबंधित किए गए कार्य

शोध में पाया गया कि ग्राम पंचायत ने कुछ कार्य गांव में किए हैं जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध बेटियों के सामाजिक समावेशन से देख सकते हैं जैसे गांव में स्नातक स्तर का महाविद्यालय खुलवाना। ग्रामीणों की ओर से शिकायत प्राप्त होने पर महाविद्यालय के बाहर कुछ दिनों के लिए बेटियों की सुरक्षा की दृष्टि से पीसीआर वैन तैनात करवाना, स्कूल में कक्षा में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने पर पुरस्कार देना, गांव में खेल का मैदान बनवाना इत्यादि। लेकिन ये सभी कार्य बेटियों एवं ग्रामीणों को पर्याप्त नहीं लगते। इस संबंध में बेटियों ने कुछ कार्य सुझाए जिनको ग्राम पंचायत को करना चाहिए।

बेटियों द्वारा सुझाए कार्य

क्र.सं.	बेटियों की संख्या प्रतिशत में	सुझाए कार्य
1.	30 प्रतिशत	विद्यालय संबंधी
2.	30 प्रतिशत	मूलभूत सुविधाओं संबंधी
3.	05 प्रतिशत	सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था
4.	15 प्रतिशत	खेल व्यवस्था संबंधी
5.	09 प्रतिशत	पुस्तकालय की व्यवस्था
6.	06 प्रतिशत	कोचिंग सेंटर व अन्य एकेडमी
7.	05 प्रतिशत	अन्य

शोध में पाया गया कि ग्राम पंचायत ने कुछ कार्य तो किए हैं परंतु गांव की बेटियां चाहती हैं कि उनके लिए ग्राम पंचायत को अभी बहुत से कार्य और करने चाहिए। इसमें विद्यालय के माहौल का बेटियों के लिए अच्छा करना, वहां पढ़ाई को सुनिश्चित करना एवं प्रत्येक व्यवस्था को विद्यालय के अंदर दुरुस्त करना प्रमुख है। बेटियों के अनुसार ग्राम पंचायत को गांव में हर प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें बिजली, पानी, सड़क प्रमुख है। बेटियों का कहना था कि अगर पानी की समुचित व्यवस्था नहीं होगी तो उन्हें ही दूर से पानी लाना पड़ेगा। बिजली की समुचित व्यवस्था करने का कार्य भी ग्राम पंचायत को करना चाहिए। गांव में बेटियों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व भी ग्राम पंचायत को लेना चाहिए एवं उनकी सुरक्षा के लिए गांव की गलियों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने चाहिए। बेटियों के लिए गांव में ही खेलों की सुविधा भी ग्राम पंचायत को देनी चाहिए और लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग–अलग खेल एकेडमी होनी चाहिए, ऐसा बेटियों का कहना था।

बेटियों के अनुसार गांव में ग्राम पंचायत को एक लाइब्रेरी की व्यवस्था केवल लड़कियों के लिए करनी चाहिए ताकि वह ठीक से पढ़ाई कर सके। गांव में ही आर्ट एंड क्राफ्ट सीखने की, नाच गाना सीखने की व्यवस्था ग्राम पंचायत को करनी चाहिए। शोध में पाया गया कि कुछ बेटियां तो बेटियों के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करने में भी पंचायत की भूमिका देखती है।

शोध में पाया गया कि अभी भी गांव में बालिकाओं की सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी पर्याप्त नहीं है और उसके लिए पर्याप्त अवसरों की, सुविधाओं की भी भारी कमी है। स्थानीय स्तर पर इन सुविधाओं में वृद्धि कर ग्रामीणों को बेटियों के प्रति जागरूक कर उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने का कार्य ग्राम पंचायत कर सकती है। अगर ग्राम पंचायत समुचित योजना बनाकर, बेटियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर कार्य करे तो निश्चित रूप से बेटियों के सामाजिक समावेशन को विस्तार दिया जा सकता है। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि ग्राम पंचायत ने बेटियों के सामाजिक समावेशन के संबंध में बहुत ही

कम कार्य किए हैं और उसके बहुत कुछ करने की बेटियों की अपेक्षा है। ग्राम पंचायत की गांव के स्तर पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने में, बेटियों के सामाजिक समावेशन में प्रभावी भूमिका हो सकती है। अतः ग्राम पंचायत को अपनी भूमिका सकारात्मक ढंग से निभानी चाहिए।

गांव में बेटियों के सामाजिक समावेशन हेतु सुझाव

शोध में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा किए गए कार्य पर्याप्त नहीं है। उन्हें गांव में बेटियों के सामाजिक समावेशन की दृष्टि से बेटियों के सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने हेतु निम्न कार्य मुख्य रूप से करने चाहिए एवं साथ ही साथ प्रदेश सरकार को भी ग्राम पंचायत को इस दिशा में और अधिक सजग बनाना चाहिए।

ग्राम पंचायत के सदस्यों का बेटियों के सामाजिक समावेशन हेतु ओरिएंटेशन करना

हरियाणा प्रदेश सरकार को सभी ग्राम पंचायत सदस्यों का बेटियों के सामाजिक समावेशन हेतु ओरिएंटेशन एक अभियान स्तर पर प्रारंभ करना चाहिए। ग्राम पंचायत सदस्यों की ही सोच अगर बेटियों के सामाजिक समावेशन के संबंध में उदासीन होगी तो ग्रामीणों को वह कैसे जागरूक कर पाएगी। ग्राम पंचायत को बेटियों के सामाजिक समावेशन की आवश्यकता एवं महत्त्व को विस्तारपूर्वक समझाना चाहिए और इसके लिए कार्यकलाप एवं अन्य गतिविधियां समयबद्ध ढंग से सुनियोजित करनी चाहिए ताकि ग्राम पंचायत बेटियों के सामाजिक समावेशन का महत्त्व समझ सके।

ग्राम पंचायत के सदस्यों के शैक्षिक स्तर को बढ़ाना

प्रदेश सरकार को ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं निर्धारित की हुई हैं उनमें बढ़ोतरी करनी चाहिए। शिक्षा और समझ का सकारात्मक सहसंबंध देखा गया है। अतः शिक्षा के स्तर में बढ़ोतरी होने से ग्राम पंचायत सदस्यों की बेटियों के प्रति सकारात्मक समझ विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है।

ग्राम पंचायत के सदस्यों एवं ग्रामीणों को बेटियों के सामाजिक समावेशन के संबंध में जागरूक करना

हरियाणा प्रदेश सरकार को बेटियों के सामाजिक समावेशन के प्रति ग्राम पंचायत को जागरूक करना चाहिए एवं साथ ही साथ ग्राम पंचायत को गांव के लोगों को भी इस संबंध में जागरूक करना चाहिए और स्वयं ग्राम पंचायत को और गांव वालों को अपनी बेटियों के प्रति लैंगिक पक्षपातपूर्ण सोच का त्याग करना चाहिए।

गांव को नशा मुक्त करने की दिशा में कदम

ग्राम पंचायत को चाहिए कि वह गांव से नशे को दूर करें। ग्रामीणों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराएं और नशे के चंगुल में फंसे ग्रामीणों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करे। नशा मुक्त गांव बेटियों के लिए सकारात्मक प्रभाव डालेगा। उसकी घर से बाहर की गतिविधियों, कार्यों में भागीदारी को बढ़ावा देने वाला सिद्ध हो सकता है।

बेटियों के लिए सुरक्षित माहौल बनाना

ग्राम पंचायत को बेटियों के सामाजिक समावेशन हेतु सुरक्षा देनी चाहिए, सुरक्षित माहौल देना चाहिए, बेटियों को यह विश्वास हो, अभिभावकों को यह विश्वास हो कि अगर वह, उसकी बेटी घर से बाहर जाएगी तो वह सुरक्षित है। सुरक्षा का माहौल बेटियों के न केवल आत्मविश्वास में वृद्धि करने वाला सिद्ध हो सकता है साथ ही साथ उनकी भागीदारी, सामाजिक गतिविधियों में बढ़ावा देने वाला हो सकता है।

ग्रामीण स्तर पर बेटियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना

बेटियों के लिए गांव में ही खेलों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी उनके सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने में सहायक हो सकती है। गांव के ऐसे माहौल में जहां बेटियां घर से बाहर अकेली निकलती नहीं हैं, अगर खेलों के प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था होगी तो यह निश्चित रूप से बालिकाओं की प्रतिभा को बाहर लाने में सहायक होगी।

पुस्तकालय एवं शौक तथा रुचि संबंधित व्यवस्था गांव में करना

ग्राम पंचायत को बेटियों के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था गांव में करनी चाहिए ताकि उनकी शिक्षा को बढ़ावा मिले एवं इसके साथ–साथ बालिकाओं की रुचि एवं शोक को बढ़ावा देने के लिए मार्गदर्शन, सहयोग एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था गांव में ही करनी चाहिए।

मूलभूत सुविधाओं की निरंतर आपूर्ति की व्यवस्था करना

ग्राम पंचायत को गांव में जल, बिजली इत्यादि मूलभूत सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए क्योंकि इनकी आपूर्ति में बाधा का खामियाजा सर्वाधिक स्त्रियों को ही भुगतना पड़ता है। अतः बालिकाओं के सामाजिक समावेश को बढ़ाने हेतु इन मूलभूत सुविधाओं की निरंतर आपूर्ति की व्यवस्था ग्राम पंचायत को करनी चाहिए।

शोध में पाया गया कि ग्राम पंचायत में केंद्र सरकार एवं हरियाणा प्रदेश सरकार द्वारा बनाई योजनाओं, कार्यक्रमों के प्रति जोकि बेटियों के सामाजिक समावेशन से संबंधित है, उनके सषक्तीकरण से संबंधित है, के प्रति जागरूकता का लगभग अभाव है। योजनाओं की पर्याप्त जानकारी का भी अभाव ग्राम पंचायत सदस्यों में पाया गया। जब ग्राम पंचायत को बेटियों के सषक्तीकरण से संबंधित योजनाओं की पर्याप्त जानकारी ही नहीं होगी तो वह ग्रामीणों को इसका लाभ लेने हेतु कैसे जागरूक कर पाएगी। दूसरे, शोध में यह भी पाया गया कि ग्राम पंचायत ने अपने स्तर पर भविष्य के लिए कोई भी, किसी भी प्रकार की योजना, कार्यक्रम एवं नीति नहीं बनाई हुई थी जिससे कि गांव में बेटियों की सामाजिक सहभागिता को बढ़ाया जा सके। अतः निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत को केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई बालिकाओं की सहभागिता एवं सषक्तीकरण एवं समावेशन से संबंधी विभिन्न योजनाओं, नीतियों एवं कार्यक्रमों की न केवल पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए अपितु साथ ही साथ ग्रामीणों को भी इसके संबंध में जागरूक किया जाना चाहिए। ग्राम पंचायत की भूमिका ऐसी योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। ग्राम पंचायत को अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए।

अंत में इस शोध के आधार पर यह कहा जा सकता है कि गांव में बेटियों के सामाजिक समावेशन में ग्राम पंचायत की भूमिका अत्यधिक महत्त्वपूर्ण होती है। अगर ग्राम पंचायतें अपनी इस भूमिका को समझ सके और उसका ठीक से निर्वहन करे तो निश्चित रूप से गांव में बेटियों की सहभागिता में बढ़ोतरी होगी और वह उसके सषक्तीकरण को बढ़ावा देगा। ग्राम पंचायत को भी राज्य द्वारा बेटियों के सामाजिक समावेशन के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए। अतः कहा जा सकता है कि ग्राम पंचायतें बेटियों के सामाजिक समावेशन की दृष्टि से अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है और वे बेटियों के सामाजिक समावेशन में बहुत ही प्रभावी भूमिका अदा कर सकती हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. Census 2011. India. https://www.census.2011.co.in

2. District Jhajjar, Government of Haryana. https://jhajjar.nic.in and Census of India 2011. (2011).
3. Haryana. https://haryana.gov.in
4. List of villages in Bahadurgarh Tehsil of Jhajjar (HR)/Village info.in https://villageinfo.in>...Jhajjar
5. Profile-Literacy - Know India. https://Knowindia.india.gov.in>lite...
6. Sex Ratio - Press Information Bureau https://pib.gov.in>Print Release.